व्यापक परामर्श हुआ है, लेकिन मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है और वह यह है कि जिस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय बढ़ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है और हम अपने जो राज्य केंद्रित विश्वविद्यालय हैं, उनमें छात्रों को प्रवेश नही दे पा रहे हैं और छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस स्थिति में निजी विश्वविद्यालय के प्रति इस शिक्षा नीति में क्या नीति अपनाई जा रही है, जिससे एक समतुल्य बना रहे? इसके साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि निजी विश्वविद्यालयों में जो फी का स्ट्रकचर है और सिलेबस है, क्या दोनों पर सरकार का नियंत्रण हो पाएगा या नही?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, इस समय इस देश के अंदर एक हजार से भी अधिक विश्वविद्यालय हैं, 45 हजार से भी अधिक डिग्री कॉलेज हैं। हम लोगों ने यह कोशिश की है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो परामर्श कार्यक्रम रखा है, उसके अंतर्गत रैंकिंग में जो विश्वविद्यालय या महाविद्यालय ऊपर आता है, उसके इर्द-गिर्द जो पाँच महाविद्यालय या विश्वविद्यालय होंगे, वह उनका मार्गदर्शक बनेगा और उनको उस रैंकिंग पर लाने के लिए जो-जो भी व्यवस्थाएं उनको चाहिए, वे सभी उनको हम देंगे। इस कारण से अभी तक 800 महाविद्यालयों को स्वायत्तता दी गई है और इस सरकार की यह मंशा है कि संस्थाओं को स्वायत्तता दी जाए ताकि वे आगे बढ़ सकें।

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, कोई भी नीति तब तक कोई बड़ा सुधार नही कर सकती है, जब तक कि शिक्षा के क्षेत्र में योग्य गुरुओं की तलाश नही होगी और जब तक तक योग्य गुरु नही मिलेंगे। जिस तरह से दीपक अंधकार को दूर कर देता है, वैसे ही जो ज्ञानी गुरु होता है, वह विद्यार्थी के अज्ञान को दूर करता है। इस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि उस क्वालिटी के टीचर्स उपलब्ध नही हैं। क्या माननीय मंत्री जी कोई इस तरह का मापदंड निर्धारित करेंगे, जिससे बेहतर किस्म के टीचर्स उपलब्ध हो सकें, क्योंकि जब तक अध्यापक सही किस्म का नही होगा, तब तक आप यह शिक्षा नीति या कोई भी नीति लाइए, वह कारगर हो ही नही सकती है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, प्रोफेसर साहब स्वयं ही शिक्षक हैं और बहुत ही योग्य शिक्षक हैं। श्रीमन्, मैं उनको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अच्छे अध्यापक कैसे रहें, निष्ठा, जिसकी चर्चा की, और उच्च शिक्षा में अर्पित, जो बाकायदा हर वर्ष ट्रेनिंग करेगा और देगा तथा यदि वे उस आधार पर नही आते हैं, तो उनको पदोन्नति नही दी जाएगी, यह already शुरू कर दिया है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Question No. 260.

Implementation of Shaala Darpan Initiative in KVs

*260. SHRI SANJAY SETH: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government is implementing Shaala Darpan initiative in Kendriya Vidyalayas (KVs);

(b) if so, the details thereof and aims and objective of this initiative;

(c) problem faced by Government under the scheme during the last three years;

(d) the status of first phase of Shaala Darpan;

(e) whether Government has circulated to the States for introduction of similar system in State Government schools, if so, the response of the State Governments thereto; and

(f) whether Government has made any arrangement for providing mobile access to parents to monitor the child's progress and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI RAMESH POKHRIYAL 'NISHANK'): (a) to (f) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) has implemented Shaala Darpan initiative in 1099 Kendriya Vidyalayas (KVs). The aims and objectives of this initiative inter-alia include addressing academic and administrative requirements of various stakeholders such as students, teachers, management and parents through a single integrated software platform, recording information of all the activities of the students, maintaining the service records of all the teaching and non-teaching staff, making the school information system transparent and efficient and providing academic inputs to teachers and students.

Problems faced during implementation *inter-alia* include issues of speed of software, delayed delivery of services by the agency.

(e) Yes, Sir. The concept of the programme was circulated to the States / UTs in September, 2015 for their consideration and further action regarding introduction of similar system in the State Government schools. In this regard, mixed responses have been received from States / UTs.

(f) No, Sir.

श्री संजय सेठ: सर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जैसे कमजोर बच्चों के लिए कोचिंग की अलग से व्यवस्था होती है, तो क्या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए भी केंद्रीय विद्यालयों में कोचिंग की व्यवस्था की गई है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं, यदि वे थोड़ा - सा कमजोर होते हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त क्लासेज़ चलाते हैं और यह प्रावधान सभी जगह है। माननीय सदस्य को इस बात को जानकर खुशी होगी कि आज केन्द्रीय विद्यालय, देश के सर्वोत्तम विद्यालयों में हैं और उनका जो प्रतिशत है, जो रिज़ल्ट है, वह लगभग 99 और शत प्रतिशत रहता है।

श्री संजय सेठ: सर, दूसरा प्रश्न यह है कि ऑडिट से यह पता चला है कि कुछ विद्यालयों की हालत बहुत खराब है, उनकी बिल्डिंग की हालत बहुत खराब है, तो आपने यह उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों में देखा है और उसके लिए कितना पैसा दिया है?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, उत्तर प्रदेश में 118 केन्द्रीय विद्यालय चल रहे हैं। आज 105 का भवन बना है और 83 अभी अस्थायी रूप में हैं। हमारे नौ विद्यालय निर्माणाधीन हैं। मैं समझता हूँ कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश के लिए हम लोगों ने 720 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Hon. Minister, let the reply also be to the point.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, मरम्मत के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, ताकि जो जर्जर विद्यालय हैं, उनको ठीक किया जा सके।

DR. PRABHAKAR KORE: Sir, my specific question is about the Kendriya Vidyalayas. Most of the Kendriya Vidyalayas are in districts or bigger cities. The quality of education in our country, particularly in the rural areas, is almost zero. Is the Government planning to open Kendriya Vidyalayas at smaller places, say, at the taluka levels, so that the rural students can get good quality education?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, केन्द्रीय विद्यालयों के लिए निर्धारित है कि जहाँ केन्द्रीय कर्मचारी रहते हैं - उनके लगातार स्थानातंरण होते हैं और उनके बच्चों को प्रवेश की समस्या रहती है, इसलिए उनको खोलने के लिए एक निर्धारित मानक है। जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का प्रश्न है, उनके लिए हमारे देश के अंदर सभी जिलों में नवोदय विद्यालय हैं, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे उच्च शिक्षा, उत्कृष्ट शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल वोरा: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने प्रश्न में कहा है कि the Kendriya Vidyalaya Sangathan has implemented Shalla Darpan initiative in 1099 Kendriya Vidyalayas and the aims and objectives of the initiative inter alia include addressing academic and administrative

requirements. Since the Shalla Darpan initiative has been implemented in 1099 Kendriya Vidyalayas, what is the progress in this regard?

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, यह जो शाला दर्पण पोर्टल है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है कि अभिभावक, बच्चा और अध्यापक एक ही प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रगति को देख सकें। उसमें बच्चे की सारी प्रगति रिपोर्ट भी होगी और बच्चा क्या कर रहा है, यह भी उसमें अंकित होगा। इससे अभिभावक घर पर ही देख सकेंगे कि उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है। श्रीमन्, 1,000 से भी अधिक विद्यालयों में यह शुरू किया गया है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI MOTILAL VORA: I would like to know the progress. ...*(Interruptions)*... What is the progress? ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Please, please. He will give the reply. ...*(Interruptions)*...

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, उसकी प्रगति अपेक्षित है। उसके संबंध में कभी-कभी जो शिकायतें आ रही हैं, वे लोड के कारण हैं, क्योंकि उस पर एक साथ बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है। इस दिशा में भी अपेक्षित कार्रवाई हो रही है, लेकिन यह पोर्टल बहुत अच्छा है और हम सभी विद्यालयों में इसको लागू करना चाहते हैं।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: My simple point is that you are allotting only ten seats to the Members of Parliament. There is a heavy demand in Tamil Nadu. Please consider to raise this quota, at least, in the State of Tamil Nadu. Please do it, at least, for Tamil Nadu KVS. Please do it.

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक': श्रीमन्, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा के बारे में भी इनकी बहुत चिन्ता रहती है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु में जो नवोदय विद्यालय हैं, वे सभी जिलों में जरूर खुलें। उसके लिए जितनी धनराशि की कमी होगी, उसको सरकार देने को तैयार है, ताकि वे आगे बढ़ सकें।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Thank you. Now, Question No. 261.

प्रारूप नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का प्रसार

*261. **श्री हरनाथ सिंह यादव**: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में संस्कृत, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं को विदेशी भाषाओं की तुलना में हेय दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है; और